

छत्तीसगढ़ मंत्रपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

24 नवंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ज़िला खनजि संस्थान नयिम 2015 में संशोधन कयि जाने के नरिणय सहति कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

प्रमुख बदि

- ज़िला खनजि संस्थान नयास से संपादति अधोसंरचना के कार्य पर व्यय हेतु नयास नधि में प्राप्त राशि से नश्चिति प्रतशित राशि के बंधन से मुत्त कयि जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ ज़िला खनजि संस्थान नयिम 2015 में संशोधन कयि जाने का नरिणय लयि गया है । इसके तहत डीएमएफ के अन्य प्राथमकिता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतशित सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतशित अधिसूचित क्षेत्र में व्यय कयि जाने के प्रावधान को समाप्त कर दयि गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक वकिस तेज़ी से होगा ।
- राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं नजि नविशकों के मध्य संपादति त्रपिक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापति वनोपज आधारति उद्योगों द्वारा जो उत्पाद नरिमाण कयि जाएंगे । छत्तीसगढ़ हरबल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतशित की छूट के साथ करय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से वकिरय हेतु शासन द्वारा नरिणय लयि गया है ।
- इस नरिणय के फलस्वरूप उन उद्योगों को जो वनोपज आधारति उत्पादों का नरिमाण करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा । इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हरबल के अंतर्गत अचछी क्वालिटि के उत्पादों का वकिरय हो सकेगा ।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचति जातयों, अनुसूचति जनजातयों और अन्य पछिड़ा वर्गों के लयि आरक्षण संशोधन वधियक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि गया ।
- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन वधियक के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि गया ।
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का वधिानसभा में उपस्थापन के लयि छत्तीसगढ़ वनियोग वधियक 2022 का अनुमोदन कयि गया ।
- प्रदेश के वभिन्न न्यायालयों में वचिराधीन साधारण प्रकृति के प्रकरणों को जनहति में वापस लयि जाने हेतु नरिधारति अवधि 31 दसिंबर, 2017 को बढ़ाकर 31 दसिंबर, 2018 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि गया ।
- मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ कयि जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयि गया ।
- भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परपितर खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वभिग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन कयि गया ।